खुशी की बात है कि इस प्रकार की घटना नहीं हुई लेकिन दुःख है कि यह घटना हुई है इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । केवल पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यह हिन्दुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी भी है उस समझौते के अनुसार जो देश का बटवारे के समय किया गया था । वहां के अल्पसंख्यकों हिन्दुओं की सुरक्षा न हो और वे भाग कर दोबारा यहां आएं यहां ऐसी स्थिति पैदा हो, तनाव पैदा हो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । हम आज चाहते हैं और पाकिस्तान कम से कम कहता है, चाहता है कि हमारे बीच में दोस्ती हो । दोस्ती केवल सरकारों के बीच में नहीं होती दोस्ती दोनों देशों के नागरिकों के बीच में भी होती है । इस प्रकार की घटनाएं होने से इस दोस्ती के बीच में रुकावट पैदा होती है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि राजनयिक स्तर पर डिप्लोमेटिक लेवल पर इस बात को ले हो सके तो सदन को यह जानकारी दें कि यह घटना क्यों हुई और आगे न हो इस तरह की सावधानी बरतने के लिए पाकिस्तान की सरकार के साथ राजनयिक स्तर पर इस मामले को लिया जाना चाहिये ।

REFERENCE TO THE REPORIED IN REASE IN THE PRICE OF L.P.G. STOVE

DR. M. M. S. SIDDHU (Uttar Pra-desh): Sir, I would like to draw the attention of the Government to the racket by which the consumers are being fleeced by the dealers of L.P.G. stoves. The *modus operandi* is that the manufacturers are giving 20 per cent commission and a promise of a free trip to U.K. or the U.S.A. for 14 days with free board and lodging on sale of 500 stoves. A motorcycle is offered for the sale of 400 stoves and a refrigerator for 200 stoves. According to the Consumer Society of South Delhi, the price of this L.P.G. stove has been raised by Rs. 130 per stove.

Now, this type of racket in the name of incentives for creat(ion of more sales is detrimental to the interest of the consumers. Earlier, Sir, the Indian Oil Corporation used to maintain a strict control on the price of stoves. Now they have some how or the other not taken this into consideration and the result is that arbitrary fleecing of the consumer by the manufacturers and the dealers is taking place. Tliis is a serious matter where the interests of the consumers should be protected, and it should be seen that the price of the stoves are reasonable and within the reach of the people. Thank you, Sir.

RF.FERENCE TO THE WHEAT PRICE FIXED BY GOVERNMENT

श्री राम नरश (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं गेहूं के दाम के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भारत सरकार ने गेहूं का दाम 142 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है । जबकि गेहूं का लागत मूल्य 200 प्रति क्विंटल आता है । भारत सरकार बाहर से गेहूं मंगाती हैं तो माननीय कृषि मंत्री जी के मुताबिक बंदरगाहों पर आकर उसका लागत मूल्य रुपये 196.40 पैसे पड़ता है और वह हमारे बाजार में आकर सवा दो सौ रुपये से कम नहीं पड़ेगा । हमारा गेहूं 142 रुजये से लेक 162 मेंसचकाच बेच, और वह गेहूं सवा दो सौरुपये की लागत पर बाजार में लाकर 162 रुपये पर बेचेगी, यानी 60 रुपये प्रति क्विंटल घाटा उठाकर बेचेगी, अगर यही घाटा हिन्दुस्तान के किसान को दिया जाता तो हिन्दुस्तान अन्न के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाता और विदेशी मुद्रा भी बचती तथा

[श्री राम नरेश]

यह रोना भी नहीं रहता । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन् 1974 में गेहूं का दाम 2 सौ रुपये प्रति क्विंटल था, यूरिया का दाम 52 रुपये इस्पात का दाम उस समय 1061 प्रति टन था आज 4310 रुपये हो गया है, इसके दाम चार गुना बढ़े, सीमेंट का दाम तीन गुना बढ़ा है, मिट्टी के तेल का दाम कई गुना बढ़ा, रेल के किराये चार गुने बढ़े हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य सन् 71 से आज तक 16 गुना बढ़ा है । इसलिए जब सभी हमारी लागत की चीजों का दाम बढ़ता गया और जो माल हम बेचते हैं, पैदा करते हैं उसका दाम घटता गया तो क्या इसका असर अगले उत्पादन पर नहीं पड़ेगा । मैं समझता हूं कि किसान घाटा सहने के लिए क्यों गेहूं बोयेगा, आगे से वह अपना अटेंशन, अपना ध्यान दूसरी फसलों की ओर ले जायेगा जिसमें कि मुनाफा हो । लेकिन मैं तो कहता हूं कि पूरी खेती ही बिना लाभ की है । हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं शायद ही किसी के सामने कोई ऐसा उदाहरण हो कि जिसकी खेती पर अगर बाहर से चाहे किसी अन्य साधन से पैसा न लगाया जाता हो भर्ती के रूप में । तो इसमें कोई लाभ नहीं है सिवाय घाटे ही घाटे के । इसलिए किसान खेती करना छोड़कर दूसरे रोजगार में जाना चाहते हैं लेकिन वहां भी उनको मौका नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो घाटा उसी व्यापार में विदेशी गेहूं खरीद करके उठा रही है अगर वही पैसा देशी किसानों को दिया जाय तो अनाज में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाती और आगे भी उसकी कोई कमी नहीं पड़ती । लेकिन इस सरकार को सिवाय बदमाशी करने के, किसानों को सबक सिखाया जाय, बाहर से गेहूं मंगा करके और उसको सस्ता बेचकर किसानों के गेहूं के दाम को नीचा किया जाय, किसानों को बरबाद किया जाय सिवाय इसके सरकार को कोई मंशा नहीं है गेहूं के दाम को कम करने में..... (**समय** की घंटी)

एक बात और कहना चाहता हूं। ए.पी.सी. आपका सफेद हाथी है, चाहे इसको पाले हुए हैं, क्या जरूरत है । कभी भी यह सही रिपोर्ट नहीं देता । सरकार के मुताबिक ही, उनके कथन के अनुसार ही न गन्ने का दाम तय हुआ है, न गेहूं का दाम तय हुआ, न अन्य किसी चीज का दाम तय हुआ, हमेशा राजनीतिक आधार पर तय किया जाता है और इस में वे ही लोग हैं जिनका खेती से कोई नाता नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सफेद हाथी पाल करके व्यर्थ का पैसा जनता का आप बरबाद करेंगे । वहां बुद्धि विलास करना देश की खेती के साथ दुश्मनी करना, सिवाय इसके ए.पी.सी. का कोई काम नहीं है इसलिए इसको तोड़ दिया जाय और खेती को भी उद्योग समझ करके सदन की एक कमेटी बैठा दी जाय, दोनों सदनों की एक कमेटी बैठा दी जाय। हमारे लागत खर्च को जोड़ लिया जाय और इसको जोड़ने के बाद हम को ज्यादा मुनाफा न दिया जाय तो कम से कम पांच परसेंट मुनाफा दिया जाय और जितना मन कहे दाम तय कर दिया जाय... । लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि सरकार सारे साधन.... ।

उपसभाध्यक्ष (डा. रफीक जकरिया) श्री लाखन सिंह ।

श्री राम नरेश : बस एक मिनट । सारा खर्चा करने के बाद भी सरकार के किसी भी फार्म में मुनाफा नहीं होता, फिर हमारा कैसे मुनाफा मान लिया जाता है ।

श्रीमन्, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी का या फार्म का खर्चा यहां सही-सही पेश कर दिया जाए, तो मालूम हो जाएगा कि कितना खर्चा होता है और हमको आप कितना देते हैं।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आपसे कहता हूं कि देश के किसानों में गहरा असंतोष है और गेहूं का मूल्य कम से कम दो सौ रुपया क्विंटल किया जाए और जो घाटा सरकार विदेशी व्यापार से उठाती है, वह किसानों को देकर, और वर्तमान मूल्य पर गेहूं बाजार में बिकवाए।

श्री हुक्म देव नारायण यादव (बिहार): चलिए, ए० पी० सी० यानी एंटि प्राइजिंग कमेटी।

REFERENCE TO THE ALLEGED WIDESPREAD IMMORALITY AMONGST STUDENTS IN JNU HOSPITAL

श्री लाखन सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिल्ली में स्थित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में व्याप्त अनैतिकता, व्यभिचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह समाचार हिन्दुस्तान में 26 तारीख को छपा है।

"देश में उच्च शिक्षा का एक प्रतिष्ठित केन्द्र समझा जाने वाला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय वास्तव में कुछ राजनीतिज्ञों, उनके छुटभाइयों, नवधनाढ्य परिवारों के बिगड़े हुए लड़कों, विदेशियों के लिए ऐशो-आराम का साधन जुटाने का एक अड्डा बना हुआ है।"

शाम होते ही चहल-पहल होने लगती है। आठ बजे का जब समय हो जाता है, तो विदेशी कारें, स्कूटर्ज, मोटर साइकल और हिन्दुस्तानी कारें वहां आने लगती हैं। विशेष रूप से होस्टल के आसपास तो खास चहल-पहल रहती है। वह केवल छात्राओं के होस्टल है।

दूसरा होस्टल आधा छात्रों का और आधा छात्राओं का है। गाड़ियां आकर के यहां अधिक देर रुकती हों, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मिलने का समय पहले ही तय रहता है और सम्बद्ध छात्रा को लेकर गाड़ियां तुरन्त वापिस चली जाती हैं। बताया जाता है कि ले जाई गई छात्रा को शाम किसी पंच-तारा होटल में गुजराने के लिए दो सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक दिये जाते हैं।

इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की अनैतिकता का वातारण फैले, इसकी जिम्मेवारी वहां के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी है। दस बजे बाद चहल-पहल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर छात्र-छात्राएं हर समय बाहर आते-जाते देखे जा सकते हैं। यही नहीं काफी हाउस में भी शाम के समय सिग्रेट में चरस भर कर दम खींचते हुए छात्र देखे जा सकते हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को सब सुविधाएं प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए, बीस रूपये महीने पर कमरा मिलता है और खाने के सौ रुपये लेते हैं, जो अच्छे से अच्छा होटल में मिलता है, उसी प्रकार का खाना वहां मिलता है। फैलोशिप के लिए सात सौ रुपया महीना मिलता है और इसके अतिरिक्त एक वर्ष के लिए अतिरिक्त खर्चे के लिए भी तीन हजार रुपये दिये जाते हैं। इसके बावजूद आज जो देश में पंच-तारा होटल की संस्कृति पनप